शुगर के फ्यूचर्स ट्रेड पर रोक के खिलाफ सेबी

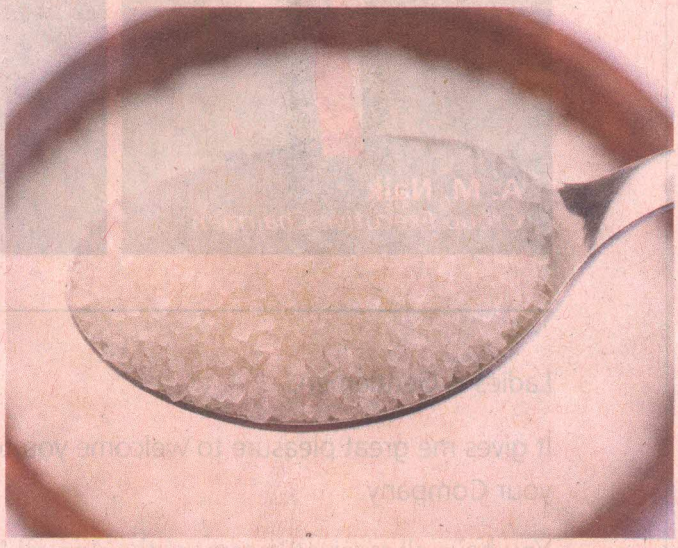

[राम सहगल | मुंबई]

सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सेबी शुगर के फ्यूचर्स ट्रेड पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए सरकार को मनाने को कोशिश कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक महीना पहले चना के फ्यूचर्स ट्रेड पर रोक लगा दी थी। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने शुगर को फ्यूचर्स ट्रेड से डीलिस्ट करने की मांग उठाई है। मिनिस्ट्री का कहना है कि फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस मूवमेंट का शुगर के स्पॉट प्राइसेज पर बड़ा असर पड़ता है।

सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ दिनों पहले सरकारी अधिकारियों को बताया था कि शुगर पर स्टॉक लिमिट से इसका फ्यूचर्स ट्रेड बढ़ा है। अगर शुगर फ्यूचर्स को स्टॉक लिमिट से छूट दी जाए तो इससे मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी और कुछ ट्रेडर्स प्राइसेज में हेरफेर नहीं कर सकेंगे। हालांकि, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि खासतौर पर फेस्टिव सीजन और उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कंज्यूमर और फूड डिपार्टमेंट्स इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। ईटी इस बारे में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर राम विलास पासवान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स सी आर चौधरी से संपर्क नहीं कर सका। इस सीजन में चीनी का उत्पादन 11 पर्सेंट घटने के अनुमान की वजह से दिल्ली में चीनी के दाम वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 40 पर्सेंट बढ़कर 42 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। हालांकि, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा का दावा है कि मौजूदा सीजन की शुरुआत (1 अक्टूबर, 2015) पर चीनी के 91 लाख टन के ओपनिंग बैलेंस से उत्पादन में कमी की भरपाई हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे देश में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ ही दिल्ली और कर्नाटक में में चीनी पर स्टॉक लिमिट लगने से मिलें फ्यूचर्स मार्केट में हिस्सा लेने से बच रही हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'सेबी के प्रस्तावों में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के तहत फ्यूचर्स मार्केट को स्टॉक लिमिट से छूट देना शामिल है।'

कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने शुगर को फ्यूचर्स ट्रेड से डीलिस्ट करने की मांग उठाई है। मिनिस्ट्री का कहना है कि फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस मूवमेंट का शुगर के स्पॉट प्राइसेज पर बड़ा असर पड़ता है

ET टिप्पणी

फ्यूचर्स मार्केट में सुधार की जरूरत

हमें शुगर सहित कमोडिटीज के लिए फ्यूचर्स मार्केट में बदलाव करने की जरूरत है। इसके तहत कमोडिटी फ्यूचर्स में इंस्टीट्यूशनल भागीदारी और सेबी के पास रजिस्टर्ड फॉरेन इनवेस्टर्स को अनुमति दी जा सकती है। हमें पोजीशन लिमिट्स और कॉन्ट्रैक्ट साइज को भी उदार बनाने की जरूरत है। इसके अलावा प्राइस और क्वांटिटी कंट्रोल पर भी दोबारा विचार करना होगा। मार्केट को बेहतर बनाने के बाद फ्यूचर्स काउंटर में कोट्स का इस्तेमाल पॉलिसी से जुड़े कदम उठाने के लिए किया जा सकता है।

The Economic Times
29/8/16